

Rajesh

क्रम संख्या-159 (23)

पंजीकरण संख्या-यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018-2020



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 नवम्बर, 2019 ई0

कार्तिक 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-6

संख्या 368/XXVII(6)/तीन/1211/2016/2019

देहरादून, 21 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0-21

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों की एकीकरण नियमावली, 2019 के प्राविधानों के क्रम में गठित लेखा परीक्षा विभाग के 'उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा संवर्ग' में नियुक्त कार्मिकों की सेवा-शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2019

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2019" है।
- (2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रारिथति

2. उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिकारी सेवा, एक राजपत्रित राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषा

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिनका एकीकरण किया गया हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है; तथा

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा संवर्ग" से सहकारिता समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों के एकीकरण नियमावली, 2019 के प्राविधानों के अनुसार समूह 'क' और 'ख' के कार्मिकों के एकीकरण के फलस्वरूप गठित 'उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा संवर्ग' अभिप्रेत है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा इस हेतु जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

भाग दो-संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
 (2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है, परन्तु
 (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
 (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थायी पद का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(1) सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी:-

(क) 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु, एकीकरण के पश्चात् सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु वर्ष 2019-20 में उपलब्ध समस्त रिक्तियों (सीधी भर्ती के पदों सहित) को केवल एक बार के लिए पदोन्नति हेतु अर्ह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(2) उप निदेशक:-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक निदेशकों/लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) संयुक्त निदेशक:-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप निदेशक के रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और राजपत्रित लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से।

(4) अपर निदेशक:-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा और राजपत्रित लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग में कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से श्रेष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिये भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक,

अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसके अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

भाग चार-अर्हताएँ

शैक्षिक अर्हताएं

8. सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट से चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) की उपाधि होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अभ्यर्थी को जिसने-

- (1) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु की गणना, जिस वर्ष पद विज्ञापित किये जाते हैं की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु यह और कि आयु के संबंध में व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित नियमों एवं आदेशों के अनुसार तदनुसार स्वतः परिवर्तित मानी जाएगी।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति में पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति-

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो:-

परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाए की ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता—

13. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल हो गया है।

परन्तु यह कि The Right of Persons With Disabilities Act-2016 (अधिनियम संख्या-49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा-33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस नियमावली के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के अनुज्ञा के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मगायेंगे। आवेदन पत्र भुगतान कर (यदि कोई हो) आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- (2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात नियम 6 के अधीन "उत्तराखण्ड राज्य" के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस संबंध में आयोग द्वारा मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों में जोड़ें जायेंगे।
- (4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो

लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिकित्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी: प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(2) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 तथा उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझें तो व्यक्ति का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयन किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता कम, जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, में चयनित व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये, तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे कि नियम 5(1)(क) एवं (ख) विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ:-नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति हेतु संस्तुत व्यक्तियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

परीक्षा

19. (1) सेवा के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परीवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परीवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को परीवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त हैं।

(2) जहां राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां इस नियमावली के अधीन की गई यह घोषणा को, कि संबंधित व्यक्ति ने परीवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता समय समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि**वेतनमान**

22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहां विदित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अधिकारी की वेतनवृद्धि केवल विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोक दी जाये तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वेतनवृद्धि की अनुमति, जिस मास में परीक्षा आयोजित की जाये उसके आगामी मास के प्रथम दिनांक से प्रदान की जायेगी और ऐसी अवधि की, जिसके दौरान वेतनवृद्धि रोकी जाय, समयमान में वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।

भाग आठ-अन्य प्राविधान**पक्ष समर्थन**

24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किन्हीं अन्य साधनों से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

✓ सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

26. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वह आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्युक्त रीति से कार्यवाही करने के **लिये आवश्यक समझें, अभिलुप्त या शिथिल कर सकती है।**

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनकी सरकार से इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

निरसन एवं निष्प्रभाव्यता

28. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप 'उत्तराखण्ड सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों के एकीकरण नियमावली, 2019' के प्राविधानों के अधीन 'उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा संवर्ग' में एकीकृत कार्मिक एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त किये गये कार्मिकों की सेवा-शर्तें उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2019 से प्रशासित होगी।

परिशिष्ट:- 'क'

(नियम-4(2) के अनुसार)

क्र०सं०	पदनाम	पद संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	निदेशक	01
2.	अपर निदेशक	02
3.	संयुक्त निदेशक	04
4.	उप निदेशक	06
5.	सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी	28
	योग	41

परिशिष्ट:- 'ख'

(नियम-22(2) के अनुसार)

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान (रु० में)
(1)	(2)	(3)
1.	निदेशक	आई0ए0एस0 संवर्ग
2.	अपर निदेशक	123100-215900 लेवल-13
3.	संयुक्त निदेशक	78800-209200 लेवल-12
4.	उप निदेशक	67700-206700 लेवल-11
5.	सहायक निदेशक / लेखा परीक्षा अधिकारी	56100-177500 लेवल-10

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 368/XXVII(6)/Three/1211/2019, Dehradun dated November 21, 2019 for general information:

No. 368/XXVII(6)/Three/1211/2019

Dated Dehradun, November 21, 2019

NOTIFICATIONMiscellaneous

In exercise of the Power Conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to regulate the service conditions of the personnel appointed in the Uttarakhand Audit Gazetted Service Cadre of the Audit Department formed in accordance with the provisions of unification of personnel of Co-operative Societies, Panchayat Audit Department and Local Fund Audit Department Rules, 2019.

The Uttarakhand Audit Gazetted Service Rules, 2019

Part I- GENERAL

- | | |
|------------------------------|---|
| Short title and commencement | 1. (1) These Rules may be called "Uttarakhand Audit Gazetted Service Rules, 2019".
(2) It Shall come into force at once. |
| Status of the service | 2. The Uttarakhand Audit officer Service is State Gazetted service Comprising Group 'A' and Group 'B' Posts. |
| Definitions | 3. Unless there is anything adverse in the subject or Context, In these rules:-
(a) ' Appointing Authority ' means the Governor;
(b) ' Citizen of India ' means a person; who is or is deemed to be a Citizen of India under part-2 of the constitution;
(c) ' Commission ' means the Uttarakhand Public Service Commission;
(d) ' Constitution ' means the Constitution of India;
(e) ' Government ' means the State Government of Uttarakhand;
(f) ' Governor ' means the Governor of Uttarakhand;
(g) ' Member of The Service ' means a Person appointed in a substantive capacity under the provision of these rules or of rules or order in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service, who has been unified;
(h) ' Recruitment Year ' means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calender year;
(i) ' Service ' means the Uttarakhand Audit Gazetted Service;
(j) ' Service Cadre ' means Uttarakhand Audit Gazetted Service Cadre which is created by unification of personnel of group 'A' and group 'B' of Co-operative Societies and Panchayat Audit Department and Local Fund Audit Department as unification rules, 2019.
(k) ' Substantive Appointment ' means an appointment on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by the one active instructions issued by the Government; |

Part II- CADRE**Cadre of Service**

4. (1) The strength of service and of each category of post there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of service and that of each category of posts there in shall until orders varying the same are not issued under sub rule (1), be such as is given in the Appendix 'A' to these rules. Provided that
- (i) the Appointing Authority may leave any vacant posts unfilled or the Governor may hold the same in abeyance without entitling any person to claim compensation (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider necessary.

PART-III RECRUITMENT**Source of Recruitment**

5. Recruitment on the various post of cadre shall be done from the following sources.

(1) Assistant Director/ Audit Officer.

(a) 50 percent by direct recruitment through Commission.

(b) 50 percent by promotion through Commission on the basis of seniority subject to rejection of unfit from such substantively appointed Assistant Audit Officers who have completed 05 year of service as Assistant Audit officer on the first day of recruitment year.

Provided that, after unification of personnel of both the departmental cadre, one time promotion on all the vacancies (including direct recruitment) of selection year 2019-20 through commission on the basis of seniority subject to rejection of unfit from such substantively appointed Assistant Audit Officers.

(2) Deputy Director- By promotion from amongst such substantively appointed Assistant Directors/Audit Officers who have completed seven year of service, on the first day of the recruitment year on the basis of seniority, subject to rejection of unfit through the Departmental Promotion Committee.

(3) Joint Director- By promotion from amongst such substantively appointed Deputy Director who have completed five years of service in that capacity and have completed total fifteen year of service in the

gazetted Audit Service Cadre on the first day of the recruitment year on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the Departmental Promotion Committee.

(4) Additional Director- By promotion from amongst such substantively appointed Joint Director who have completed 03 years of service in that capacity and have completed total twenty years of service in the Gazetted Audit Service Cadre on the basis of merit through Departmental Promotion Committee.

Reservation

6. Reservation to the candidates belonging to Scheduled Castess, Schuduled Tribes, Other Backward Classes, Economicaly Weaker Classes and Other Categories of Uttarakhand shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of Recruitment.

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post of the service must be-
 - (a) a citizen of India or
 - (b) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling In india or
 - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Shri Lanka or any of the east African counries of Kenya, Uganda and The United Republic of Tanzania (formarly Tanganika and Janjibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to catagory (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligiblity has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) with also be required to obtain a certificate of eligiblity granted by the Deputy Inspector of Police, Intelligence branch, Uttarakhand.

Provided further also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligiblity will be issued for a period of more than one year and the retention such a candidate in service be on the period of one year, shall be subject to is acquiring Indian citizenship.

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

PART-IV QUALIFICATION

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Director/ Audit Officer must hold a degree in commerce (B.com) from a recognized university or institute of India established by law or chartered Accountant (C.A) degree from institute of chartered accountant of India.

Preferential Qualification

9. A candidate who has
(1) served in the territorial army for a minimum period of two year, or
(2) obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on July 1st of the calender year in which recruitment is to be made,
Provided that the upper age limit, in case of candidates belonging to Schedule Caste and Schedule Tribe, Other Backward Classes and such other catogory of the state of Uttarakhand as may be notified by Government from time to time, shall be greater by such number of year as may be specified;
provided also that in relation to the rules promulgated for provision of age by State Government from time to time shall deemed to be modified itself.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in government service the appointing authority shall satisfy itself in this regard.

Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service, any person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12. A male candidate who has more than one wife living and female candidate who has more than one husband living, shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a medical board.

Provided that subsequent to section 33 of the Right of person with Disabilities Act, 2016 (Act, 49 year 2016 GOI) the post identified for this and the categories identified under section-34 the disabled shall not be denied the appointment as per rules.

Provided further that the examination by medical board shall not be necessary in case of a candidate appointed by promotion.

Part- V PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Delemination of vacancies 14. The appointing authority shall determine and intimate to the commission the number of vacancies to be filled during the course of the recruitment year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Schedule Caste, Schedule Tribes Other Backward Classes Economical Weaker Section and Other Categories under rule 6 of these rules.

Procedure for Direct Recuritment 15. (1) The commission shall invite applications for permission to appear in the competitive examination in the prescribed application forms, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment (if any).

(2) No candidate shall be admitted to the examination without admit card issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination has been received and tabulated the Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribes, Other Backward

Classes, Economically Weaker Section and other categories under rule 6, call for interview such number of candidates who have secured marks as per the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order to their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidate as they consider fit for appointment.

if two or more candidates obtained equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall to be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies. the Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note : Syllabus and rules for the Competition examination shall be prescribed by the Commission from time to time.

Procedure of Recuritment by 16.
promotion

(1) Recruitment to the post of Assistant Director/Audit Officer shall be done by promotion as per the provision of Public Service Commission Consultation Selection (Process) Rules, 2003 (as amended from time to time) on the basis of seniority subject to rejection of unfit through selection committee.

(2) Recruitment to the post of Additional Director, Joint Director and Deputy Director shall be done by promotion as per the standard fixed through the Departmental Promotion Committee constituted as per the provision of "Uttarakhand (procedure of selection for promotion in the state reviews (outside the purview of the Public Service Commission) rules, 2013" and "Uttarakhand Departmental Promotion Committee (for the post out side the purview of public service commission) Rules, 2002".

(3) Appointing authority shall prepare a list of eligible candidates and put up the same to the selection committee alongwith there annual confidential entries and other record consider appropriate.

Combined Selection list

17. If appointment is done through direct recruitment and promotion both in one recruitment year then a combined selection list shall be prepared including names from corresponding list so that the percentage prescribed in rule 5(1) (a) and (b) may be maintained. First name in the list shall be of the person appointed through promotion.

PART VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. The Appointing Authority shall make appointment of the persons recommended in the order in which they stand in the list prepared under rule 15, 16 or 17 as the case may be.

Probation

19. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
(2) The appointing authority may on reason to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that the probation period shall not be extended for more than one year and in any condition, for two years, except in exceptional circumstances.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or the end of the period of probation or extended period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under subrule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary

- capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to taken into account for the purpose of computing the period of probation
- Confirmation** 20 (1) Subject to provision of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if
- (a). He has passed the prescribed departmental examination,
 - (b). He has successfully undergone the prescribed training,
 - (c). His work and conduct are reported to be satisfactory,
 - (d). His integrity is certified and ,
 - (e). The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation,
- (2) Where confirmation is not necessary under the provisions of the Government Servant Confirmation Rules of the State, in that case a declaration made under these rules that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation .

- Seniority** 21 Except as provided in this rules, the seniority of a person substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servant (determination of seniority) Rules, 2002 as amended from time to time.

Part VII- PAY ETC

- Pay scales** 22 (1) The scales of pay admissible to persons appointed to a post in service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix "B"

- Pay during probation** 23 (1) Not withstanding any contrary provisions in the fundamental rules a persons on probation, if he is not already in permanent government service shall be given his first increment when he has completed one year of satisfactory service, and where prescribed has passed departmental examination and undergone training. Second increment after two year of service shall be given only when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfactory performance, such period of extension shall not be

counted for increment unless the appointing authority directs otherwise

(2) The pay during probation of a persons, who was already holding a post under the government, shall be regulated as per the relevant principal rules.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction then such extended period shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent government services shall be regulated by the relevant rules generally applicable to government servants, serving in connection with the affairs of the State.

(4) If the increment of the officer is with held during the probationary period only on account of failure to pas the departmental examination, it shall be allowed to him/her from the first day of the month following the month in which the examination is held and the period during which the increment is with hold, shall be counted for increment in the time scale.

Part VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing

24 No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for a appointment.

Regulation of other matter

25 In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to service be governed by the rule, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation of the conditions of service

26 Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service, cause undue hardship in particular case not withstanding anything contained in the rules applicable to the case, it may be order being consultation of the Commission, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just an equitable manner.

Provided that where any rule is made with consultation of Commission there the requirement of that rule shall be dispensed with or relax with the prior consultation with the commission.

Saving

27

Nothing in these rules shall effect reservations and other concession required to be provided for the Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes And Othe Special Categories of Persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Repeal and non effectiveness

28

Consequent upon the implementation of these rules, personnel unified in Uttarakhand Audit Gazetted Service cadre under the provision of 'Uttarakhand Co-operative Societies and Panchayat Audit Department and Local Fund Audit Department' personnel Unification Rules, 2019 and conditions of service of personnel appointed under these rules shall be administered by the Uttarakhand Audit Gazetted Service rules, 2019.

Appendix No. 'A'
(According to rule 4(2))

Sr.no	Name of The Post	Number of Posts
1	2	3
1.	Director	01
2.	Additional Director	02
3.	Joint Director	04
4.	Deputy Director	06
5.	Assistant Director/Audit officers	28
	Total	41

Appendix No. 'B'
(According to rule 22(2))

Sr.no	Name of The Post	Scale (Rs.)
1	2	3
1.	Director	IAS Cadre
2.	Additional Director	123100-215900 (level-13)
3.	Joint Director	78800-209200 (level-12)
4.	Deputy Director	67700-206700 (level-11)
5.	Assistant Director/Audit officers	56100-177500 (level-10)

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.